भारत सरकार

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 669**

जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2026 को दिया जाना है।

31 आषाढ़, 1948 (शक)

## पैक्स सिलिका एलायन्स

**669. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीरः**

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निवेश को आकर्षित करने, उन्नत प्रौद्योगिकी सुरक्षित करने और घरेलू सेमी-कंडक्टर विनिर्माण एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए पैक्स सिलिका एलायन्स का लाभ उठाने हेतु कोई रोडमैप तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो सेमी-कंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण, प्रसंस्करण और परिशोधन के लिए भारत की सीमित क्षमता के परिवर्धन के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने वैश्विक प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं में भाग लेने के इच्छुक भारतीय उद्योग जगत, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर कड़े सुरक्षा ऑडिट, निर्यात प्रतिबंधों और आपूर्ति-श्रृंखला अनुपालन नियमों के संभावित प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)**

**(क)** से **(ग):** भारत विश्वसनीय, लचीली और विविध वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए दिनांक 20 फरवरी, 2026 को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के मौके पर पैक्स सिलिका एलायंस में शामिल हुआ।

सरकार उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने और सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महत्वपूर्ण खनिजों, अनुसंधान, नवाचार और प्रतिभा विकास में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भागीदार देशों के साथ साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए एक रणनीतिक मंच के रूप में गठबंधन का लाभ उठा रही है।

सरकार ने उपरोक्त दृष्टिकोण के साथ 25-26 जून 2026 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित तीसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया।

सरकार ने 2025 में 'नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन' (एनसीएमएम) को मंज़ूरी दी है। इसके लिए 16,300 करोड़ रुपये का खर्च प्रस्तावित है और उम्मीद है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और अन्य स्टेकहोल्डर्स इसमें 18,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। इस मिशन का मकसद ज़रूरी खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) की लंबे समय तक टिकाऊ सप्लाई सुनिश्चित करना और भारत की क्रिटिकल मिनरल वैल्यू चेन को मज़बूत करना है। इसमें मिनरल की खोज और माइनिंग से लेकर बेनिफिशिएशन, प्रोसेसिंग और इस्तेमाल के बाद बचे उत्पादों से रिकवरी तक के सभी चरण शामिल हैं।

सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए 56 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों और 11 अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है, जिसमें महत्वपूर्ण खनिजों के 6 ब्लॉक शामिल हैं।

सरकार ने सख्त सुरक्षा ऑडिट, निर्यात नियंत्रण उपायों और आपूर्ति-श्रृंखला अनुपालन आवश्यकताओं और भारतीय कंपनियों के लिए उनके संभावित प्रभावों सहित विकसित हो रहे वैश्विक विनियामक परिदृश्य का संज्ञान लिया है। इन मुद्दों को पारदर्शी, विश्वसनीय और अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की दृष्टि से पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन, भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) और अन्य रणनीतिक संवादों सहित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से लगातार उठाया गया है।

सरकार भारत सेमीकंडक्टर मिशन, डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना, इलेक्ट्रॉनिक्स संघटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस), इंडियाएआई मिशन और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से घरेलू उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के उपायों को भी लागू कर रही है ताकि एमएसएमई सहित भारतीय कंपनियों को वैश्विक गुणवत्ता को पूरा करने और वैश्विक प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके।

*****